Food Problem in India (Part-B)

वर्तमान में सरकार की खाद्य नीति निम्नानुसार है :→

(i) खाद्यान्नों का आयात :→ अपनी वर्तमान खाद नीति के अन्तर्गत सरकार खाद्यान्नों के आयात में कम-बद के साथ निरन्तरता बनाए हुए है।

(ii) खाद्यान्नों उत्पादन को बढ़ावा :→ खाद्यान्नों की उत्पादन बढ़ाने कि दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। उसके द्वारा अनेक ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनसे उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त है।

(iii) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था :→ बजार में खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धि उपभोक्ताओं के बीच बनाए रखती है।

(iv) सुरक्षित भण्डार व्यवस्था :→ सरकार देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए खाद्यान्नों का भण्डारण करती है।

(v) जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण :→ सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या

पर नियन्त्रण लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि देश की ..... अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार खाद्यान्नों की उपलब्धता भी इससे प्रभावित होती है।

खाद्य समस्या के समाधान हेतु सुझाव :→
यदि खाद्यान्न की दृष्टि से सम्पूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो देश में खाद्य समस्या जैसी कोई स्थिति नहीं है थोड़े बहुत मूल्यों के उतार-चढ़ाव के साथ जनसामान्य को खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहती है।
खाद्य समस्या के समाधान के लिए निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं :→

(i) खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि :→ खाद्यसमस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया जा सकता है, कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जाए।

(ii) भूमि कानूनों की शीघ्र क्रियान्वयन :→
सरकार द्वारा अब तक भूमि सुधारों की दिशा में जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका क्रियान्वयन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया जाना चाहिए इन कानूनों से प्राप्त हुई अतिरिक्त भूमि वंचित भूमिहीन किसानों में वितरित की

Scanned with CamScanner

जानी चाहिए।

(iii) फसलों की सुरक्षा :→ सरकार एवं किसान को फसलों की सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार जब फसल खेतों से कटकर खलिहान में आ जाती है तो उसे चूहों, आग, हवा एवं अन्य संकटों से बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए।

(iv) मूल्यों पर नियन्त्रण :→ सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि खाद्यान्नों के मूल्यों में कम-से-कम उतार-चढ़ाव हो। इसके लिए प्रत्येक व्यापारी के पास खाद्यान्न भण्डारण की एक सीमा निश्चित होनी चाहिए।

(v) सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली :→ सरकार द्वारा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता को सम्पूर्ण वर्ष उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त होता रहे। देश के छोटे-से-छोटे भाग में राशन की दुकानें खोली जानी चाहिए और इन दुकानों का आवश्यक खाद्यान्नों का भण्डार उपलब्ध होना चाहिए।

(vi) खाद्यान्न वसूली :→ सरकार की ओर से ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि किसान अपना खाद्यान्न सरकार को बेचने के लिए स्वेच्छा से तत्पर रहे।

Scanned with CamScanner

(vii) जमाखोरी की नियन्त्रण :→ खाद्यान्न समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी हो सकता है कि सरकार खाद्यान्नों की जमाखोरी करने की प्रवृति को हतोत्साहित करे।

(viii) जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण :→ सरकार को जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए।

(ix) कृषि विभाग का दायित्व :→ देश एवं प्रदेश के कृषि विभागों का यह दायित्व है कि वह समय-समय पर कृषि पद्धति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराते रहे।

(x) उपभोक्ताओं की प्रवृति में बदलाव :→ खाद्य समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता की ओर से भी सहयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार माँसाहारी व्यक्तियों को अपने भोजन में मछली, अण्डा, माँस आदि का उपयोग अधिक बढ़ाना चाहिए। समाज में विवाह, मृत्युभोज जैसी परम्पराओं पर बड़े-बड़े भोज दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जिससे अन्न का होने वाला अपव्यय व बर्बादी को रोका जा सके।

Scanned with CamScanner